>

Title : Need to declare all the pending irrigation projects in Vidharba region as National Projects.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं विदर्भ से निर्वाचित हुआ हूं। इस क्षेत्र में किसान आत्महत्या बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये विशेष आर्थिक पैकेज तथा की गई ऋणमुक्ति के बाद भी किसानों द्वारा आत्महत्या बदस्तूर जारी है। यहां के किसानों की समृद्धि के लिए सिंचाई के साधन और सिंचाई परियोजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है। विदर्भ पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है। राज्य सरकार द्वारा विकास का अनुशेष कायम रखने से क्षेत्र की जनता अब केन्द्र सरकार से आस लगा कर बैठी है। हमारे यहां पर वनक्षेत्र अधिक होने से वन संरक्षण कानून के कारण बड़ी संख्या में सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के अभाव में लंबित रहती है। इस क्षेत्र के किसानों का सिंचाई सुविधा से वंचित रहने का यह प्रमुख कारण है और उनके पिछड़ेपन का यही कारक है। बरसों से परियोजना लंबित रहने से इसका निर्माण मूल्य भी लगातार बढ़ता है। इसी तरह वनक्षेत्र की हानि का एन.पी.वी के रूप में हर्जाना भरने की शर्त के कारण भी राज्य सरकार यहां की सिंचाई परियोजना के लिए उपेक्षा बरत रही है। सिंचाई के अभाव में वर्षाजल पर निर्भर खेती के कारण विदर्भ के किसानों द्वारा आत्महत्यायें की जा रही हैं, यह वास्तव में कृषि आयोग के अध्यक्ष डॉ0 स्वामीनाथन ने भी स्वीकार किया था। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कोई उपचारात्मक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं जिस तरह गोसीखुर्द परियोजना को केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। उसी तर्ज पर विदर्भ की सभी लंबित परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में सरकार मान्यता प्रदान करे तथा इसके निर्माण हेतु बड़ी राशि उपलब्ध कराये और अन्य छोटी सिंचाई परियोजना का निर्माण सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्र सरकार स्वयं इसके लिए धनराशि का विशेष आबंटन करे। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए सिंचाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार तथा जल संसाधन मंत्रालय से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।